रख-रखाव तथा कृषकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है।

(ii) कृषि में प्लास्टिक के उपयोग संबंधी अन्य योजना में सरकार द्वारा ग्रीनहाउस, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग आदि के लिए, जो अच्छी क्वालिटी के फूलों के उत्पादन के लिए उपयोगी है, सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी सरल ऋण सहभागिता योजनाओं के माध्यम से पुष्प फसलों के उत्पादन तथा कटाई पश्चात रख-रखाव के लिए समेकित परियोजनाओं को सहायता दी जाती है।

(iv) सरकार ने पुष्प फसलों के बीजों/रोपण सामग्री के थोक आयात संबंधी प्रक्रियाओं को आसान और सरल बना दिया है, जिनका आयात अब आयात परमिट एवं शुल्क की अदायगी के बगैर किया जा सकता है।

(v) वाणिज्य मंत्रालय आधारभूत ढांचे के सृजन, विपणन प्रोत्साहन एवं हवाई भाड़ा सब्सीडी संबंधी योजनाओं के माध्यम से फूलों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता प्रदान करता है।

(vi) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नई किस्मों के विकास एवं विभिन्न पुष्प फसलों की कृषि तकनीकों के मानकीकरण हेतु अनुसंधान प्रयासों को मजबूत बनाया गया है।

दूध का उत्पादन

4079. **श्री राम जेठमलानी:** क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री 2 अगस्त, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2070 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत केवल 160 ग्राम है जबकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की खपत कम से कम 250 ग्राम निर्धारित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में एक गाय प्रतिदिन 1.5 किलोग्राम दूध देती है जबकि विश्व के अन्य देशों में प्रति गाय दूध का औसत उत्पादन 20 से 30 लीटर तक है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रति गाय दूध की मात्रा बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सभा में दिनांक 2.8.1996 को दिए अतारांकित प्रश्न सं॰ 2070 के उत्तर के अनुसार, 1995-96 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति दूध की (अनुमानित) उपलब्धता 197 ग्राम प्रतिदिन है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंशित पोषणिक आवश्यकता 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है।

(ग) जी, नहीं। खाद्य एवं कृषि संगठन के 1994 के आंकलन के अनुसार भारत में विश्व के 5.60 किलोग्राम के औसत की तुलना में प्रति गाय प्रतिदिन की औसत उत्पादकता 2.70 किलोग्राम बैठती है। विश्व के अन्य देशों में प्रति गाय का औसत दुग्ध उत्पादन बंग्लादेश में 0.56 किलोग्राम से लेकर संयुक्त अमरीका में 17.0 किलोग्राम तथा इस्राइल में 25.7 किलोग्राम तक के बीच है।

(घ) और (ङ) जी, हां, केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से आनुवांशिक उन्नयन, आहार/चारे की उपलब्धता में सुधार आदि के द्वारा दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Dwindling of Elephant Population

4080. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A PARMAR:
SHRI SHUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the growth of population of elephants is dwindling in the country;

(b) if so, the State-wise population of elephants according to the last three animal census and the rate of growth and increase in number registered during each census period;

(c) in which States the population of elephants has been notably dwindling; and

(d) the steps being taken to arrest this decline and with what success?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JA1 NARAYAN PRASAD NISHAD): (a) No, Sir. The comparison between estimates of wild elephant population as per 1985 report of Asian Elephant Specialist Group, 1UCN, 1989 report of Dr. R. Sukumar, Centre for Ecological Studies, Indian Institute of Science, Bangalore and 1993 compilation of elephant population by Government of India, the population of wild elephants in India hasshown an overall increase, even though between 1989 and 1993 there is a decline in their population in north-east India.

(b) and (c) A complete state-wise comparison for the three all-India level census is not available because the 1985 and 1989 reports presented population estimates partly region-wise and partly state-wise. Statement I gives the comparison accordingly, *(see below)* The States of Arunachal Pradesh and Meghalaya have indicated reduction in estimated population of 1993 over the reported average of 1989.

(d) The. Government of India have taken, inter alia, the following steps to ensure maintenance of viable population of wild elephants in their natural habitats, and the overall success is indicated by the rise in the country's total wild elephant populations:

(i) Project Elephant has been launched in 1991-92 to provide financial assistance to the elephant range states for protection of elephant populations, conservation and ecological restoration of their habitats and corridors, and mitigation of conflicts between elephants and human population residing in and around elephant habitats.

(ii) The Indian elephant has been placed in Schedule I of the Wildlife Protection Act, 1972, under which it has been provided maximum possible protection by law.

(iit) The trade in ivory has been banned to discourage poaching of elephants for their tusks. The Asian elephant is also placed in Appendix-I of Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES), in order to discourage international trade.

Statement

Population of Wild Elephants in India (Figures represent mid-values of the Range of Estimated Population)

	States Region	1985 AESG Report	1989 CES Report	% variation over 1985	1993 GOI Report	% variation over 1989
	SOUTH INDIA					
1.	Andhra Pradesh				46	N.A.
2.	Karnataka				5500	N.A.
3.	Kerala				3500	N.A.
4.	Tamilnadu				2400	N.A.
	TOTAL EAST	6412	6950	-1- 8.39%	11446	+64.69%
	INDIA					
5_,	Bihar		335		550	64.18%
6.	Orissa		1650		1750	6.06%
	TOTAL	1635	1985	+21.41%	2300	+15.86%

	States Region	1985 AESG CES Report	1989 Report	% variation over 1985 GOI	1993 Report	% variation over 1989
	N. E. INDIA					——
7.	Arunachal Pradesh		3150		2500	-20.63%
8.	Assam (incl. Nagaland)		3500		5500	+57.14%
9.	Meghalaya		3287		2750	-16.33%
10.	West Bengal		155		200	+29.03%
1.	Tripura		135			N.A.
	TOTAL	10468	12227	+16.80%	10950	-10.44%
	N. W. INDIA					
2.	Uttar Pradesh	445	525	+ 17.97%	875	+66.67%
	TOTAL	445	525	+17.97%	875	+66.67%
	GRAND TOTAL:	18960	21687	+14.38%	25571	+17.91%

मध्य प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का दुरुपयोग

4081. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:**
श्री राघवजी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उन गैर सरकारी सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं के नाम क्या है जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया गया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्था को प्रत्येक वर्ष किस-किस प्रयोजन के लिये कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग) इनमें से उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मंत्रालय को उन्हें प्रदान की गई राशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी; और

(घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान इस संबंध में लागू की गई नई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सीधे किसी गैर सरकारी सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान नहीं किया जाता है। इन संस्थानों के उद्देश्य शैक्षिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासात्मक कार्यकलाप इत्यादि हो सकते है। ऐसी संस्थाओं के नामों का केन्द्रीय रूप से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, सामान्यतः विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में एक लाख रु० और उससे अधिक के अनुदानों का ब्यौरा होता है जिसे संसद में माननीय सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान की सिफारिशें

4082. **श्री गोविन्दराव मिरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में भारत में कृषि उत्पादन में लगातार गिरावट पर अपनी चिन्ता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो अगली शताब्दी के दौरान खाद्यान्नों की मांग और आपूर्ति के संबंध में क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट "इण्डियन एग्रीकल्चर इमर्जिंग परस्पेक्टिव एंड पालिसी इशूज" (दिसम्बर 1994 अंक) में भारत में कृषि उपज में लगातार आने वाली कमी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत में खाद्यान्नों के लिए घरेलू मांग में कमी आई है जो कि मूलरूप से गैर-खाद्यान्न वस्तुओं की व्यापक किस्मों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग करने के कारण हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।